शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक-4 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 23-30 जनवरी 2023 मूल्य पांच रूपए

सुक्खू सरकार ने भी किया भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरैन्स का दावा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर यह दावा किया है कि उनकी सरकार की भी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरैन्स की नीति रहेगी। प्रदेश की हर सरकार यह दावा करने की रस्म ईमानदारी से निभाती आ रही है लेकिन व्यवहार में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इसलिये यह दावा करना एक रस्म अदायगी होकर रह गया है या सबसे छोटे कर्मचारी के खिलाफ कारवाइ से आगे नहीं बढ़ पाया है। बल्कि बड़े लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा हुआ होना एक बड़ी योग्यता बनकर बड़ी तरक्की का माध्यम बन जाता है। लेकिन यह भ्रष्टाचार ही है जो हर समस्या के मूल में खड़ा रहता है। कानूनी दॉव पेचों के जाल में भ्रष्टाचार ऐसे उलझ जाता है कि सी.बी.आई. का मामला झेल रहा व्यक्ति भी अपनी चालाकी से शीर्ष पर जा बैठता है और कोई कुछ नहीं कर पाता।

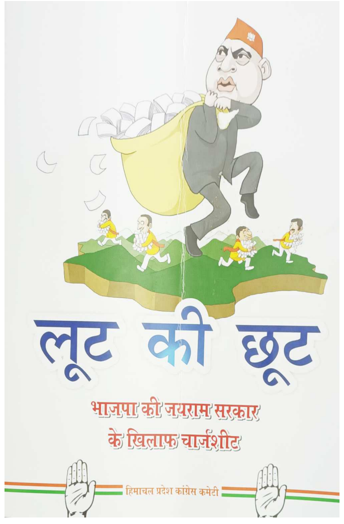

क्या सरकार 1997 में अधिसूचित रिवार्ड योजना के नियम बनायेगी या इसे वापस लेगी

क्या कांग्रेस के 27-12-2021 को राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन पर कारवाई होगी

"लूट की छूट" आरोप पत्र पर जांच कब होगी उठने लगा है सवाल

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरैन्स के परिदृश्य में 31 अक्तूबर 1997 को तत्कालीन वीरभद्र सरकार ने एक रिवार्ड योजना अधिसूचित की थी। इस योजना में यह प्रावधान किया गया था कि भ्रष्टाचार की हर शिकायत पर तीस दिन के भीतर प्रारम्भिक जांच की जायेगी और यदि शिकायत की इस जांच में मामले को आगे बढ़ाने के तथ्य मिलते हैं तो शिकायतकर्ता को उसी स्टेज पर इनाम राशि का 25% तुरन्त दे दिया जायेगा। शेष राशि जांच पूरी होने पर देने की बात की गयी। ईनाम की कुल राशि शिकायत से सरकार को होने वाले लाभ का 25% भाग रखा गया था। इस योजना के तहत कई शिकायतें सरकार के पास और विजिलैन्स के पास आयी हैं लेकिन एक भी शिकायत पर तीस दिनों के भीतर कोई प्रारम्भिक जांच तक नहीं हुई है। यहां तक कि इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद इसमें जो नियम बनाये जाने थे वह आज तक नहीं बन पाये हैं और न ही इस योजना को निरस्त किया गया है। आज भी यह योजना सरकारी रिकॉर्ड में यथास्थिति बनी हुई है। यदि इस योजना के तहत आयी शिकायतों पर ईमानदारी से अमल किया जाता तो शायद प्रदेश कर्ज के गर्भ में डूबने से बच जाता। अदालत के निर्देशों तक की अनुपालन नहीं हुई है।

आज जब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरैन्स का दावा कर रहे हैं तब भी प्रशासन उनको ऐसे मामलों की सही जानकारी नहीं दे रहा है। क्योंकि मण्डी में बन रहे शिवधाम के निर्माण हेतु मंगवाये गये 80 करोड की राशि के टैण्डर में ईएमडी केवल 20,000 ली गयी जबकि नियमों के मुताबिक यह कम से कम चालीस लाख होनी चाहिये थी। जब यह मामला उजागर होने के बाद भी इस पर कोई कारवाई नहीं हुई तब इस मामले की शिकायत विजिलैन्स में भी की गयी। विजिलैन्स ने संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के बाद मामले कि अपने स्तर पर जांच करके कारवाई करने के लिए पर्यटन निगम को भेज दिया। लेकिन पर्यटन निगम में अभी तक अपने स्तर पर न तो कोई कारवाई की है और न ही विजिलैन्स ने निगम से इस संबंध में कोई जानकारी मांगी है। ऐसी स्थिति डीजल में हुई स्मगलिंग के मामले की है। हिमाचल से झारखण्ड तक डीजल सम्गल हुआ है। मामला उजागर होने के बाद हरकत में आये तन्त्र ने नौ करोड का यह मामला बनाया है। लेकिन जिन टैंकरों से यह चोरी होती रही उनके खिलाफ कोई जांच या कारवाई नहीं हुई है। मामले को रफा-दफा करने के प्रयास हो रहे हैं।

कांग्रेस ने 27-12-2021 को प्रदेश के राज्यपाल को एक आठ पन्नों का ज्ञापन सौंपा था। इसमें सरकार के खिलाफ गंभीर हो आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गयी थी। इसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान ''लूट की छूट'' शीर्षक तले एक आरोप पत्र सार्वजनिक रूप से जारी किया था। इसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुये यह कहा गया था कि सरकार बनते ही इन आरोपों की जांच के लिये एक कमेटी गठित की जायेगी और सारे घोटालेबाज जेल जायेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद हिमाचल दिवस पर आये ब्यान के अतिरिक्त और कोई कारवाई शुरू होने का संकेत तक नहीं है। ऐसे में यह सवाल भी उठने लगा है कि यदि अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर में पेपर लीक का यह प्रकरण न घटता तो शायद वहां पर पिछले वर्षो में हुए चयन पर कोई सवाल ही उठता। क्योंकि इसी बोर्ड की तरह प्रदेश का लोक सेवा आयोग भी प्रदेश की राजपत्रित सेवाओं की चयन प्रक्रिया के तहत परीक्षाएं लेकर साक्षात्कार के माध्यम से चयन को अंजाम देता है। आयोग को लेकर भी ऐसी चर्चाएं उठती रही है कि कई परीक्षाओं के होने और उनके परिणाम घोषित करने के बाद उनके साक्षात्कार के परिणाम घोषित करने में लंबा अंतराल रहता रहा है। इस अप्रत्याशित अंतराल के कारण पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठते रहे हैं। ऐसे मामलों की जांच किये जाने की मांग भी उठती रही है। बल्कि 2018 में सदन में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का लोक सेवा आयोग को लेकर आया वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण था। परन्तु इस ब्यान के बाद कोई और कदम सामने नही आया था। आज भी लोक सेवा आयोग को लेकर इस सरकार की खामोशी से यही उभरता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा ब्यान देना हर सरकार के लिये एक आवश्यक रस्म अदायगी के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह गया है।

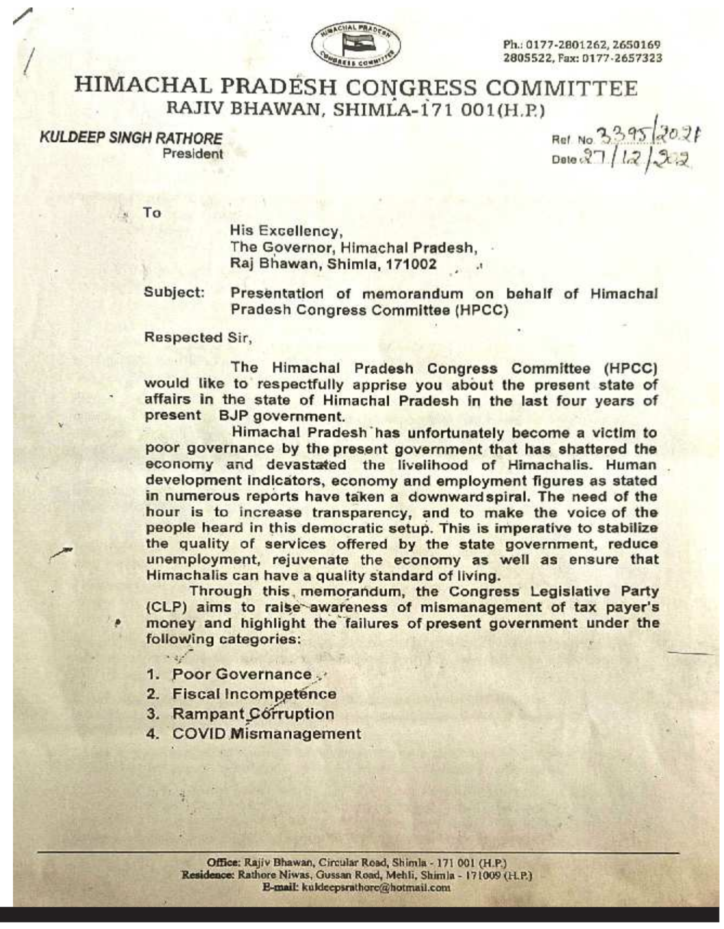

Ph.: 0177-2801262, 2650169
2805522, Fax: 0177-2657323

HIMACHAL PRADESH CONGRESS COMMITTEE
RAJIV BHAWAN, SHIMLA-171 001(H.P.)

KULDEEP SINGH RATHORE
President

Ref. No. 3395/2021
Date 27/12/2021

To

His Excellency,
The Governor, Himachal Pradesh,
Raj Bhawan, Shimla, 171002

Subject: Presentation of memorandum on behalf of Himachal Pradesh Congress Committee (HPCC)

Respected Sir,

The Himachal Pradesh Congress Committee (HPCC) would like to respectfully apprise you about the present state of affairs in the state of Himachal Pradesh in the last four years of present BJP government.

Himachal Pradesh has unfortunately become a victim to poor governance by the present government that has shattered the economy and devastated the livelihood of Himachalis. Human development indicators, economy and employment figures as stated in numerous reports have taken a downward spiral. The need of the hour is to increase transparency, and to make the voice of the people heard in this democratic setup. This is imperative to stabilize the quality of services offered by the state government, reduce unemployment, rejuvenate the economy as well as ensure that Himachalis can have a quality standard of living.

Through this memorandum, the Congress Legislative Party (CLP) aims to raise awareness of mismanagement of tax payer's money and highlight the failures of present government under the following categories:

1. Poor Governance
2. Fiscal Incompetence
3. Rampant Corruption
4. COVID Mismanagement

Office: Rajiv Bhawan, Circular Road, Shimla - 171 001 (H.P.)
Residence: Rathore Niwas, Gussan Road, Mehli, Shimla - 171009 (H.P.)
E-mail: kuldeepsrathore@hotmail.com

राज्यपाल ने रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया

शिमला/शैल। 74वां गणतंत्र दिवस पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया। राज्यपाल राजेन्द्र

विश्वनाथ आर्लेकर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली।

परेड का नेतृत्व 22-जम्मू और कश्मीर राइफल्स के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट करण गोगना ने किया।

समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी विशेष रूप से उपस्थित थे।

मार्च पास्ट में सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, गृह रक्षक, अग्निशमन सेवाएं और हिमाचल प्रदेश डाक सेवाएं, आपदा प्रबन्धन, पूर्व सैनिक, एन.सी.सी. व एन.एस.एस. और भारत स्काउट एवं गाईड की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया।

गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदेश सरकार की विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों को दर्शाती आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की गईं।

इस अवसर पर सूचना एवं जन संपर्क द्वारा लोक कल्याण एवं समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए वर्तमान राज्य सरकार के निर्णयों और महत्वाकांक्षी पहल पर आधारित नाटिका प्रस्तुत की गयी।

इस अवसर पर चंबा, हमीरपुर, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जम्मू-कश्मीर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आनी, जिला कुल्लू, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उत्तराखंड तथा जिला किन्नौर के सांस्कृतिक दलों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दीं।

कार्यक्रम में पुलिस बैंड की मनमोहक प्रस्तुति भी आकर्षण का केन्द्र रही।

पर्यटन विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

इस अवसर पर राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए सुख-आश्रय कोष में अधिक से अधिक अंशदान करने की अपील की।

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, विधायक हरीश जनारथा, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, वरिष्ठ नागरिक, पुलिस और सैन्य अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति और भारी संख्या में लोग इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने एनआरआई विद्यार्थियों के साथ संवाद किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में एशिया

नेट न्यूज चैनल के 'प्राउड टू बी एन इंडियन' कार्यक्रम 2023 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की तीन दिवसीय यात्रा पर आए मध्यपूर्वी देशों के भारतीय मूल के विद्यार्थियों से संवाद किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि विदेश में रहे भारतीय मूल के विद्यार्थी भारत के दूत की भूमिका हुए विश्व में हमारी समद्ध संस्कृति और परम्पराओं का प्रचार-प्रसार का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों का आहवान किया कि वे अपनी संस्कृति और मिट्टी से सदैव जुड़े रहें। उन्होंने कहा कि आज भारत पुनः महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, भारत के बदलते स्वरूप और भारत के विशाल लोकतंत्र जैसे विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए।

राज्यपाल ने देवभूमि में पहुंचने पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि हिमाचल की प्राकृतिक सुन्दरता और यहां का स्वच्छ वातावरण उन्हें अवश्य ही आकर्षित करेगा।

उन्होंने एशिया नेट न्यूज चैनल द्वारा टूअर आयोजित करने के प्रयासों की सराहना की।

इससे पूर्व एशिया न्यूज के मुख्य समन्वयक सम्पादक प्रशांत रघुवम्सम ने राज्यपाल का स्वागत किया और विद्यार्थियों के साथ संवाद के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने राज्यपाल से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे और गणतंत्र दिवस परेड के अनुभव भी साझा किए।

हिमाचल पुलिस के पांच अधिकारी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से सम्मानित

शिमला/शैल। यह बहुत गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि गणतंत्र दिवस-2023 के अवसर पर भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के पांच पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया है।

Smt. Satwant Atwal Trivedi, ADGP

सतवंत अटवाल त्रिवेदी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, शिमला को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित चार अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया है।

Sh. Rahul Sharma, Dy.SP

Sh. Jitender Singh, ACO

SI Inder Dutt

HC Susheel Thakur

1. राहुल शर्मा, उप-पुलिस अधीक्षक, एफ.एस.एल., जुन्गा
2. जितेन्द्र सिंह, उप-पुलिस अधीक्षक, प्रथम सशस्त्र वाहिनी जुन्गा
3. सहायक उप निरीक्षक इन्द्र दत्त, प्रथम सशस्त्र वाहिनी जुन्गा
4. मुख्य आरक्षी सुशील कुमार, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो

संजय कुन्डू, पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश ने विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किये गये सभी अधिकारियों को बहुत बधाई दी है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
अंजना

राजभवन में 'एट होम' का आयोजन

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन में 'एट होम' का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उपस्थित थे। एट होम में शहर के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, जीओसी- इन-सी आरट्रैक लेफ्टिनेंट जनरल एस.एस. महल, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पी.एस. राणा, विधायकगण, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, कुलपति, स्वतंत्रता सेनानी, शहर के प्रमुख व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, पुलिस और सैन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री ने पूर्ण राज्यत्व दिवस पर लोगों को बधाई दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश के 53वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है।

अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व का उत्सव मनाते हुए हम अपने वीर नायकों, हिमाचल निर्माता डॉ. वाई.एस. परमार और प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाली महान विभूतियों को याद करते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अविस्मरणीय योगदान रहा है और बर्फबारी के बीच 25 जनवरी, 1971 को प्रदेश की जनता को यह सौगात देने वे स्वयं शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पहुंची थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन के साथ प्रदेश का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए दृढ़-संकल्प है।

उप-मुख्यमंत्री ने पूर्ण राज्यत्व दिवस पर बधाई देते हुए राज्य के गठन एवं इसे वर्तमान स्वरूप में एकीकृत करने के लिए प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. वाई. एस. परमार एवं इस संघर्ष से जुड़े सभी नेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के कल्याण और हर क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश आने वाले समय में विकास की नई गाथा लिखेगा तथा लोगों के जीवन में सुख-समृद्धि में बढ़ोतरी होगी।

राज्यपाल ने पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेश के 53वें पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस पर प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दीं। अपने शुभकामना संदेश में राज्यपाल ने प्रदेश के लोगों की सुख और समृद्धि की कामना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी वर्षों में हिमाचल प्रदेश उन्नति के नए आयाम स्थापित करते हुए हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास करेगा।

मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य एवं समृद्धि की कामना की है।

अपने बधाई सन्देश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने सभी क्षेत्रों में आशातीत प्रगति की है जिसका श्रेय राज्य के मेहनतकश तथा ईमानदार लोगों को जाता है।

उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शक है। गणतंत्र दिवस सभी को एक सूत्र में बांधने वाली भारतीयता के गौरव का उत्सव है। मुख्यमंत्री ने लोगों से भारत को शांतिपूर्ण और प्रगतिशील देश बनने की दिशा में सदैव समर्पित होकर कार्य करने का आहवान किया।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह गर्व की बात है कि हिमाचल मुख्य क्षेत्रों में देश के अन्य राज्यों के लिए विकास का आदर्श बनकर उभर रहा है।

उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमें गणतंत्र के आधारभूत सिद्धान्तों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना चाहिए। हमें अपनी लोकतांत्रिक जड़ों को और मजबूत बनाने के लिए निरन्तर अग्रसर रहना चाहिए।

प्रदेश सरकार आशा कार्यकर्त्ताओं की उचित मांगों पर विचार करेगी: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश आशा वर्करज़ यूनियन के एक प्रतिनिधिमण्डल ने अध्यक्ष सत्या रांटा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि आशा कार्यकर्त्ता प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने तथा उनके लिए नीति बनाने की मांग रखी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड महामारी के दौरान उनकी बहुमूल्य सेवाओं को ध्यान में रखते उनकी मांगें पूर्ण करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्त्ताओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के प्रयासों की सराहना की और उनकी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी और विधायक विनोद सुल्तानपुरी उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश में विकास और परिवर्तन के नए युग का सूत्रपात हुआः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के 53वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (बाल) हमीरपुर में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, होमगार्ड, भारतीय रिज़र्व बटालियन सकोह, एनसीसी तथा स्काउट एवं गाईड की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक मार्चपास्ट की सलामी ली।

मार्चपास्ट का नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक अंकित शर्मा ने किया।

इस अवसर पर सम्बोधन के दौरान प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक हिमाचलवासी ने राज्य के विकास की लंबी यात्रा में अपना योगदान दिया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पहाड़ी राज्य की प्रगति में प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. वाईएस परमार के योगदान का भी स्मरण किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया।

इस अवसर पर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों को प्रदर्शित करती अग्निशमन एवं गृहरक्षक की झांकी, परिवहन विभाग, हिमाचल पथ परिवहन निगम, पर्यटन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, कृषि विभाग, बागवानी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, विद्युत बोर्ड, ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा उद्योग विभाग द्वारा झांकियां निकाली गईं।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कृषि मंत्री चन्द्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार) गोकुल बुटेल, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, मोहन लाल ब्राक्टा, चौधरी राम कुमार, किशोरी लाल, विधायकगण, पूर्व विधायक, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, उपायुक्त हमीरपुर देबश्वेता बनिक, पुलिस अधीक्षक आकृति शर्मा, गणमान्य व्यक्ति और भारी संख्या में लोग उपस्थित थे।

मानव कल्याण के साथ पशु, पर्यावरण और पौधे भी मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता

शिमला/शैल। मानवीय संवेदनाओं के साथ अपने सरोकारों का निर्वहन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनका दृष्टिकोण सिर्फ मानव कल्याण तक ही सीमित नहीं है। पशु, पर्यावरण और पौधे भी उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं की सूची में हैं।

मुख्यमंत्री ने जहां पर्यावरण व पौधों के संरक्षण के साथ-साथ प्रदेश को 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, वहीं बेसहारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने के लिए भी अधिकारियों को व्यापक कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 के तहत भी बेसहारा पशुओं की सूचना व शिकायत तथा समाधान प्रक्रिया को प्रभावी बनाया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व और संवेदनशील व्यक्तित्व के परिचायक हैं।

सरकार ने बजट के लिये मांगे सुझाव

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए राज्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। बजट को और अधिक लोक केन्द्रित बनाने के उद्देश्य से बजट में समाज के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता तथा विचारों का समावेश आवश्यक है। सरकार ने आम-जनमानस, उद्योगों, व्यापारिक तथा कृषक संगठनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं।

यह सुझाव 15 फरवरी, 2023 तक ई-मेल के माध्यम से budgetidea.hp@gmail.com अथवा सचिव (वित्त) के कार्यालय को पत्र के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के वैब-पोर्टल पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि बजट के लिए सुझाव राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, व्यय नियंत्रण तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर दिए जा सकते है। इससे बजट निर्माण में पारदर्शिता, खुलापन, प्रतिक्रियात्मक तथा सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।

राज्य सरकार ने की गणतंत्र दिवस पर 359 बन्दियों को विशेष मुआफी की घोषणा

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने 26 जनवरी, 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न कारागारों में सजा काट रहे बन्दियों को उनके अच्छे आचरण एवं व्यवहार के दृष्टिगत विशेष मुआफी की घोषणा की है, जिसके तहत विशेष मुआफी 7 दिन से लेकर 45 दिन तक दी गयी है।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार द्वारा दी गयी मुआफी से राज्य के विभिन्न कारागारों के 359 बन्दी लाभान्वित होंगे, जिसमें 3 बन्दी सजा पूरी होने के उपरांत 26 जनवरी को तत्काल रिहा हो जाएंगे। शिमला के कंडा कारावास के 97 व कैथू जेल के 15, नाहन के 108, धर्मशाला के 65, चंबा के 17, बिलासपुर के 18, मंडी के 10, सोलन के 04, ऊना के 11, हमीरपुर के 05, कल्पा के 03, नालागढ़ कारावास के 06 बंदियों को रिहा किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव में कार्यक्रमों की श्रृंखला में बंदियों की कुछ श्रेणियों को विशेष माफी देने और उन्हें तीन चरणों 15 अगस्त 2022, 26 जनवरी 2023 और 15 अगस्त, 2023 को रिहा करने का प्रस्ताव है। सजा माफी की योजना का उद्देश्य बंदियों में कारावास के दौरान अनुशासन और सदाचरण सुनिश्चित करना है व प्रोत्साहन के रूप में जल्दी रिहाई की सम्भावना का अवसर प्रदान करना है।

इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में जिन पात्र बंदियों ने अपनी 66 प्रतिशत सजा पूर्ण कर ली है, उसमें से 4 बंदियों को रिहा किया जा रहा है। एक बंदी जिसने अपनी कारावास की सजा पूर्ण कर ली है, लेकिन वह अपनी जुर्माना राशि देने में असमर्थ है, उस बंदी को भी रिहा किया जा रहा है। इस माफी से प्रदेश की विभिन्न कारागारों से कुल 5 बंदियों को रिहा किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना चरणबद्ध तरीके से होगी लागूः धनीराम शांडिल

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल)धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डलीय उप-समिति की बैठक आयोजित की गयी। इसमें कृषि मंत्री चन्द्र कुमार तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह तथा सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा 18 से 59 वर्ष आयुवर्ग की पात्र महिलाओं को 1500/- रुपए प्रतिमाह दी जाने वाली नारी सम्मान राशि बारे विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गयी।

डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने कहा कि परिवार की प्रगति व उत्थान में महिलाओं की भूमिका को और अधिक सशक्त करने व उनके योगदान को उचित सम्मान देने के लिए प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना को लागू किया जाएगा। उन्होंने सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों को इस योजना की पात्रता के निर्धारण पर सुझाव व परामर्श दिए तथा विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की।

उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू करने से पूर्व आर्थिक व सामाजिक पहलुओं का पूर्ण विश्लेषण किया जायेगा ताकि समाज के पिछड़े वर्ग व आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग की सभी पात्र महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाया जा सके। उन्होंने सम्बन्धित विभाग को इससे जुड़े वित्तीय पहलुओं पर भी आवश्यक सुझाव दिए।

कृषि मंत्री चन्द्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार इस योजना को लागू करने के लिए वचनबद्ध है जिसके लिए आर्थिक विश्लेषण तथा परिवार के वर्गीकरण पर गहनता से विचार किया जाना चाहिए। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश की पात्र व जरूरतमंद महिलाओं को इस योजना के तहत शामिल किया जायेगा।

बैठक में सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एम.सुधा देवी, निदेशक ईएसओएमएसए हेमराज बैरवा, निदेशक महिला एवं बाल विकास एकता काप्टा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

आपदाओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी उन्नत चेतावनी प्रणाली

शिमला/शैल। उत्तराखंड में जोशीमठ के धंसाव की हालिया घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार के अधिकारियों को आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया क्षमता प्रणाली में सुधार के लिए एक अग्रिम चेतावनी प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से भूकंप संभावित क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिलेगी और भूस्खलन एवं धंसाव वाले क्षेत्रों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में भी यह मददगार साबित होगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य में संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर तैयारियों के अलावा प्रतिक्रिया और जागरूकता प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के माध्यम से राज्य विद्युत बोर्ड को दी जा रही सहायता को बढ़ाने और राज्य आपदा राहत नियमावली में आवश्यक संशोधन करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने नई और उन्नत तकनीक के माध्यम से ग्लेशियरों का उचित मानचित्रण और भूकंप की अधिक संभावना वाले क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए भी कहा है।

हिमाचल प्रदेश अपने प्राकृतिक सौंदर्य, बर्फ से ढके हिमालय और नयनाभिराम दृश्यावलियों के लिए जाना जाता है जो हर वर्ष लाखों घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। लेकिन यहां भूस्खलन, बादल फटने और अचानक बाढ़ व अन्य प्राकृतिक आपदाओं के संभावित खतरे भी लगातार बने रहते हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय से आपदाओं के मामले में अग्रिम चेतावनी की तकनीक विकसित करने और आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने में सहायता मिलेगी।

फसल विविधीकरण को दिया जाएगा बढ़ावाःचंद्र कुमार

शिमला/शैल। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दूरदर्शिता व नई सोच के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के दृष्टिगत विभाग द्वारा क्लस्टर सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। इस सिस्टम के अंतर्गत विशेष फसल को केंद्र में रखकर किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र की मिट्टी की विशेषताओं का आकलन करने के लिए मृदा परीक्षण किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादों की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार फसल विविधीकरण को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में लैंड यूज प्लान तैयार किया जाएगा। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य क्षमता में बढ़ौतरी के लिए नई तकनीकों का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

जाइका परियोजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के हर गांव के खेत में पानी पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जाइका के अंतर्गत परियोजनाओं को तैयार कर उन्हें आजीविका के सतत् अवसर प्रदान किए जाएंगे। किसानों के उत्पादों को अच्छा बाजार उपलब्ध करवाकर उनके उत्पादों को बेहतर दाम उपलब्ध करवाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्राकृतिक उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों को नकदी फसलों के उत्पादन के साथ-साथ प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाए।

इस अवसर पर सचिव कृषि राकेश कंवर, निदेशक कृषि विभाग डॉ.बी.आर. तकी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

हमे ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। – स्वामी विवेकानंद –

सम्पादकीय

ऐसे नहीं होगा व्यवस्था परिवर्तन

हिमाचल को पूर्ण राज्य बने 53 वर्ष हो गये हैं । 25 जनवरी 1971 को प्रदेश की आबादी 3460434 थी जो आज आधार कार्ड के अनुसार 7316708 हो गयी है। 53 वर्षों के इस सफर में प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सड़क जैसे हर क्षेत्र में पर्याप्त तरक्की की है। इसमें सरकार तथा प्राइवेट सैक्टर दोनों ने पूरा योगदान दिया है। हर तरह के उद्योग प्रदेश में स्थापित हुए हैं । इस दौरान रही सारी सरकारों ने प्रदेश के विकास में भरपूर योगदान दिया है। किसी को भी कम करके आंकना सही नहीं होगा। लेकिन आज 53 वर्ष के बाद जो सरकार आयी है उसने यह घोषित किया है की व्यवस्था बदलने आयी है राज करने नहीं। सुक्खू सरकार और उनकी कांग्रेस पार्टी को यह लगा है कि अब व्यवस्था बदलने की आवश्यकता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार का नीति सूत्र व्यवस्था बदलना कहा हो। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि प्रदेश की वर्तमान स्थितियों पर एक निष्पक्ष नजर डाल ली जाये। क्योंकि व्यवस्था राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासन दोनों के तालमेल और विजन का प्रतिफल होता है। हर सरकार प्राय: अपने दृष्टि पत्र जारी करती रही है । लंबें भविष्य तक के दृष्टि पत्र प्रशासन से तैयार करवा कर जारी हुये हैं। हर सरकार ने उद्योग नीतियां बदली है। लेकिन आज तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि किसी भी सरकार ने अपने कार्यकाल के अंत इस आशय का कोई श्वेत पत्र जारी किया हो।

आज तक जो भी विकास प्रदेश में हुआ है उसके बाद आज प्रदेश 75000 करोड के कर्ज तक पहुंच गया है । कैग के मुताबिक लिये जा रहे कर्ज का 74% कर्ज की वापसी पर खर्च हो रहा है । प्रदेश के हर नागरिक पर करीब 1.25 लाख का कर्ज भार खड़ा है । इतने कर्ज के बाद भी प्रदेश बेरोजगारी में देश के पहले छ: राज्यों में शामिल है। 1971 से 1980 तक प्रदेश पर कोई कर्ज नहीं था यह 1998 में धूमल सरकार द्वारा विधानसभा सदन में रखे श्वेत पत्र से सामने आ चुका है। उसके बाद आयी किसी भी सरकार ने ऐसा श्वेत पत्र जारी करके प्रदेश की वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं करवाया है । आज सुक्खू सरकार ने भी अपने पहले ही विधानसभा सत्र में वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप पिछली सरकार पर लगाये हैं। पिछली सरकार पर करीब ग्यारह हजार करोड़ की वेतन और पैन्शन की देनदारी छोड़ने का आरोप लगाया गया है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इस कुप्रबंधन के लिये किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं की गयी है। बल्कि उसी शीर्ष प्रशासन को आगे बढ़ाया गया है जो इस कुव्यवस्था का बड़ा भागीदार रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इसी प्रशासनिक तंत्र के सहारे व्यवस्था कैसे बदली जायेगी।

कांग्रेस ने चुनाव से पहले जनता को दस गारंन्टियां जारी करके यह भरोसा दिलाया था कि वह उसकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये यह कदम उठायेगी । इस वायदे के मुताबिक मन्त्रिमंडल की पहली बैठक में इस आशय के फैसले भी लिये गये हैं। 73 लाख की आबादी में से कितनों को व्यवहारिक रुप से लाभ पहुंचेगा इसका आंकड़ा तो बाद में आयेगा । लेकिन अभी बजट से पहले ही जो डीजल के दाम और नगर निगम क्षेत्रों में पानी की दरों में जो बढ़ौतरी की गयी है उसका असर तो हर नागरिक पर पड़ेगा। युवाओं को रोजगार कैसे उपलब्ध करवाया जायेगा इसकी रूपरेखा एक मंत्री कमेटी तैयार कर रही है। लेकिन अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड से जो युवा परीक्षाएं पास करके नौकरी पाने के कगार पर पहुंच चुके थे वह अब निराश होकर आंसू बहाने पर पहुंच गये हैं। पूरी जनता ने यह आंसू देखे हैं। निकट भविष्य में इसका कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। सरकार के पास दैनिक खर्च चलाने के लिये पैसा नहीं है यह एक वरिष्ठ मंत्री का ब्यान है। इस सरकार को भी कर्ज लेकर खर्च चलाना पड़ रहा है।

सरकार की इस व्यवहारिक स्थिति के परिदृश्य में जब आम आदमी के सामने मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां और कुछ दूसरे लोगों को की कैबिनेट रैंक में हो रही ताजपोशीयां आ रही हैं तब उसका विश्वास भ्रमित होना स्वाभाविक हो जाता है। जबकि राजस्व और बिजली में ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर काम करने से प्रदेश को कर्ज से भी मुक्ति दिलाई जा सकती है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय हर व्यक्ति को निशुल्क उपलब्ध होना चाहिये और प्रदेश में यह किया जा सकना बहुत संभव है । इसके लिए सही अध्ययन और राय की आवश्यकता है। इस समय यदि सरकार ने अपने कदम नहीं सुधारें तो आने वाला समय बड़ा कठिन हो जायेगा और व्यवस्था परिवर्तन एक जुमला बनकर रह जायेगा।

बुर्जुगों की प्यार मोहब्बत की रिवायत के खिलाफ फतवे मुसलमानों की गैरत पर हमला

सूफी कौसर मजीदी

वर्ष 1947 में हमारे बुर्जुगों के पास दो विकल्प थे। एक तो जिन्ना के नापाक सपनो का पाकिस्तान और दूसरा हमारे बुजुर्गों की अजमत और वकार का निशान हिन्दुस्तान। एक तरफ मुसलमानों का कथित इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था तो दूसरी तरफ 85 प्रतिशत से अधिक हिन्दू आबादी पर आधारित पंथनिरपेक्ष हिन्दुस्तान। एक तरफ मुसलमान आस पड़ोस का माहौल रखने वाला पाकिस्तान था तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ रवायात पर अमल पैरा हिन्दू पड़ोसियों का हिन्दुतान। एक तरफ जिन्ना की खुरेज सियासत का मकबरा पाकिस्तान तो दूसरी तरफ ख्वाजा मोइउद्दीन चिश्ती का हिन्दुस्तान। चारो तरफ खूनी पसमंजर के दिल दहलाने वाले हालात थे, ऐसे में हमारे बुजुर्गों ने जिन्ना के होशरूबाई तिलस्म के मजहर मुसलमानों की हुकूमत वाले पाकिस्तान को लात मार कर 85 प्रतिशत से अधिक हिन्दू आबादी पर आधारित हिन्दुस्तान को अंगीकार किया।

अपने हम शया हिन्दुओं और दिगर मजाहिब के लोगों के सुख दुख में साथ चलने के वादों के साथ हिन्दुओं में रहने का अज्मलिया, यह जानते हुए कि मंदिरों की घंटियों की आवाजें, देवी जागरण और भागवत कथाओं के नजरों से दो–चार होना होगा, इन सब के दरमयान अपनी इस्लामी मजहबी रसुमात निभानी होगी। यह सब जानने के बाद भी हमारे बुजुर्गों ने हिन्दू आबादी को अपना बड़ा भाई समझते हुए उनके साथ अपने दामनों का वावस्ता किया और भारत की बहुसंख्यक हिन्दू आबादी ने उन्हें अपने गले से लगाया। बाराबरी के हुकूक देने हुए बहुसंख्यक हिन्दू समाज के विद्वानों की बड़ी संख्या में स्थापित संविधान सभा द्वारा भारत को पंथनिर्पेक्ष राज्य बनाते हुए मुसलमानों को बराबरी के अधिकार दिए। यही नहीं अल्पसंख्यकों को वह भी अधिकार प्रदान किए गए, जो किसी इस्लामिक देश, खासकर पाकिस्तान में सोच पाना भी संभव नहीं है।

एक बार नहीं कई बार देश ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृहमंत्री, कई राज्यों में मुख्यमंत्री और राज्यपाल सहित देश के सर्वोच्च पदों पर मुसलमानों को आसीन कराया। देश के प्रशासनिक सेवा, विदेश सेवा, तकनीकी सेवा, अभियंत्रण सेवा, कृषि सेवा आदि उच्च प्रशासनिक पदों आज मुसलमान बरे गुमान से आसीन हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, न्याय, मनोरंजन सहित हर क्षेत्र में मुसलमानों को समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। भारत के संविधान की महानता को कहां तक बखान किया जाए, मुस्लिम नेतृत्व द्वारा देश विभाजित कराए जाने की विभीषिका को स्पष्ट देखने के बाद भी भारतीय संविधान में मुस्लिम नेतृत्व के द्वार को बंद नहीं किया।

इन सब सत्य एतिहासिक तथ्यों के बाद आज जब कोई कट्टरपंथी मौलवी, मुल्ला किसी 150 साल पहले के मौलवी के फतवे की बिना पर यह कहता है कि हिन्दू के त्योहार पर मिठाई खरीदने मात्र से ही मुसलमान काफीर हो जाता है, तो मन को पीड़ा होने के साथ साथ शर्म भी महसूस होती है। भारत, इस देश की महानता और इस देश के बहुसंख्यकों की दरियादिली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बहुसंख्यकों के खिलाफ मुस्लिम धर्म गुरु फतबे जारी करते हैं और इस देश का सहिष्णु हिन्दू समाज उनके खिलाफ केवल लोकतांत्रिक और संविधान सम्मत प्रतिक्रिया मात्र व्यक्त करता है। अगर इसी प्रकार के कृत्य कोई हिन्दू या गैर मुसलमान किसी मुस्लिम देश में करे तो उसकी हत्या तय है। भारत में ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए हमें थोड़ा सतर्क तो होना ही पड़ेगा। हमारे मदसे में आज खुलेआम वो फतवे पढ़ाए जा रहे हैं, जिसके मुताबिक होली का रंग अगर जिश्म पर पड़ जाए तो अल्ला कयामत के दिन उसका उतना हिस्सा काट देगा। क्या फालतू की बात हम अपनी पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं।

एक पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में यह फतवा देना कि ''गैर मुसलमानों को उनके त्योहार पर बधाई देने से मुसलमान काफिर हो जाता है।'' हास्यास्पद है कि ऐसे आपराधिक फतवे वो मुल्ला देते हैं जो खुद अपनी विचारधारा के विपरीत मुसलमानों को काफिर मानते हैं। सच तो यह है कि संविधान विरुद्ध ये अनैतिक फतवे इंसानियत के भी खिलाफ हैं, क्योंकि हिन्दुओं के साथ मेलजोल रखना गुनाह होता तो इस्लामिक राष्ट्र के विकल्प के बाद भी हमारे बुजुर्ग भारत को अपना भविष्य नहीं बनाते।

होली के रंग से रंगदा हिस्सा काट दिया जाएगा तो बाबा बुल्ले शाह, ''होली खेलूं में पढ़ के विसमिल्ला'' न गाते और आनंद मनाते। आलमपनाह वारिश पाक अपने दर पर होली न खिलवाते, बाबा निजामुद्दीन औलिया और मखदुम शाह सफी की दरगाहों पर दिवाली के दिए न जलाए जाते। हिन्दुओं के रश्मोरिवाज अगर नाजायज और हराम होते तो चिश्ती खानकाहों पर बसंत के उत्सव न मनाए जाते। भजन सुनने से कोई काफिर हो जाता तो सैयद इब्राहिम उर्फ रसखान अब्दुल, रहीम खानखाना, मलिक मोहम्मद जायसी कभी भजन न लिखते, मौलाना हसरत मोहानी श्रीकृष्ण को कृष्ण अल्लैइस्लाम नही कहते। अल्लामा इकबाल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को इमामे हिन्द से न नवाजते।

हमारे बुजुर्ग इन सब बातों से आशना थे, यही वजह थी कि अपनी रिवायात पर अमल पैरा रहते हुए उन्होंने भारत को अपना भविष्य बनाया। आज बुजुर्गों की रूह यकीनन इन मुल्लाओं के तकफीरी फतवों को देखकर मायूस होंगी। इन बातों के आलोक में मैं भारत के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि 800 साल पहले के हमारे बुजुर्गों की प्यार मोहब्बत की नियायत, के खिलाफ मोहब्बतों को तोड़ने वाले फतबे और फरमान क्या मुसलमानों की गैरत पर हमला नहीं है?

जोशीमठः कब तक यूँ ही दरकते रहेंगे पहाड़

–डॉ राकेश कपूर–

मानव जनित इस त्रास्दि में जोशी मठ अकेला नहीं है। और कितने जोशीमठ?

जोशी मठ धंस रहा है, सड़क मकान, होटल, अस्पताल बैंक, जिधर देखो भयावह तस्वीर, लोग सकते में हैं, सद्मे में हैं, जाने कब घर मकान् दुकान धराशाही होकर गिर जाये और साथ ही न जाने कितनी जिन्दगियां। आदि शंकराचार्य ने जिस जोशीमठ से अलखद जगायी थी सनातनी संस्कृति कि, वोह अल्साया सा गांव रूपी कसबा जो न जाने कब शहर में बदल गया, और कब मानव निर्मित त्रास्दि का मन्ज़र बन कर खड़ा हो गया। वहीं जोशीमठ जो प्रवेश द्वार कहलाता है ब्रिद्रिविशाल, हेम्कुन्ठ साहिब, फूलों कि घाटी के दर्शन का, औलि का साहसिक खेल गांव, चीन् तिब्बत के साथ लगती सीमा कि रक्षा व्यवस्था का अस्तित्व अचानक विहीन होने कि और बढ़ रहा है। जोशीमठ त्रास्दि पर अचानक से पूरे देश के मीडिया और वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का ध्यान गया हो ऐसा भी नही है, इस समस्या को जनान्दोलन के रूप में जाग्रित् कर, वैश्विक पटल पर लाने में अतुल सत्ती जैसे असंख्य स्थानीय लोगों कि भूमिका है जो अब पहाड़ बचाओ आंदोलन का पर्याय बन चुके है।

जोशी मठ जैसी समस्या हिमालय के काश्मीर से लेकर मेघालय, नागालैंड, हिमाचल, उत्तराखंड सहित सभी राज्यों में विध्यमान है और कुछ में भयावह रूप ले चूकि है के कारणों को पहले विवेचित् करना आवश्यक है तभी निवारण तक पंहुचा जा सकता है।

सर्वप्रथम किसी भी क्षेत्र कि भू भौगोलिक पारस्थिकि और भुगर्भीय सन्नरचना को इस दृष्टि से परखना जरुरी होता है। इस के पश्चात् वहां पर मौजूद वो फाल्ट और थ्रस्ट जो भुकम्पीय गतिविधि के समय उससे होने वाले नुकसान के कारक बनते है, या फिर जिनके साथ निरंतर गतिविधियां बनी रहती है धीरे धीरे भुगर्भिय परिवर्तनों को सतह पर परावर्तित कर सकते है। इसके बाद चटानो और मृदा के प्रकार का अध्ययन आवश्यक हो जाता है ताकि उसकी भार वहन क्षमताए (shearing strength) का आकलन करने के पश्चात ही यह तय हो सकता है कि किसी स्थान पर कितना और कैसा निर्माण हो सकता हैं और कितनी जनसंख्या का भार वह वहन कर सकता है।

जोशीमठ के संधर्ब में भी इसी प्रकार के अध्ययनों को सूचिबद्ध कर के हिमालय क्षेत्र कि अधोसरंचनाओर भू भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टीगत ही समस्या को समझना आवश्यक है ताकि इस का स्थायी हल तथ्य्पर्क वैज्ञानिक आधार पर हो सके।

हमारा साझा विज़नः
2023 तक 5000 मेगावाट, 2030 तक 25000 मेगावाट तथा 2040 तक 50000 मेगावाट

अतुल्य एसजेवीएन @35

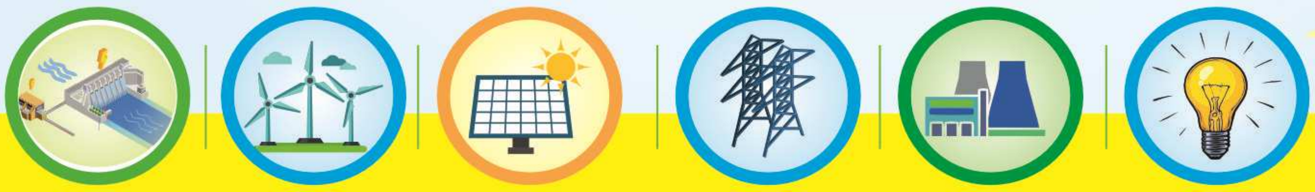

जल विद्युत | पवन विद्युत | सौर विद्युत | विद्युत पारेषण | ताप विद्युत | पॉवर ट्रेडिंग

प्रचालनाधीन परियोजनाएंः
- 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन
- 412 मेगावाट रामपुर जल विद्युत स्टेशन
- 47.6 मेगावाट खिरवीरे पवन विद्युत स्टेशन
- 5.6 मेगावाट चारंका सौर पीवी विद्युत स्टेशन
- 50 मेगावाट साडला पवन विद्युत स्टेशन
- एनजेएचपीएस में 1.31 मेगावाट ग्रिड कनैक्टिड सौर विद्युत स्टेशन
- 400 केवी, डी/सी क्रास बार्डर ट्रांसमिशन लाईन (भारतीय हिस्सा)

विकासाधीन परियोजनाएंः
- हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाएं
- भूटान में जल परियोजना
- नेपाल में जल परियोजनाएं
- बिहार में ताप परियोजना
- हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं असम में सौर विद्युत परियोजनाएं
- ट्रांसमिशन लाइनों का निष्पादन

एसजेवीएन
SJVN

एसजेवीएन लिमिटेड
SJVN Limited
(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
एक 'मिनी रत्न' एवं शेड्यूल 'ए' पीएसयू। एक आईएसओ 9001:2005 प्रमाणित कम्पनी

पंजीकृत कार्यालय : एसजेवीएन लिमिटेड, शक्ति सदन, कॉरपोरेट मुख्यालय, शनान, शिमला–171006, हिमाचल प्रदेश (भारत)
एक्सीपीडाइटिंग कार्यालय : ऑफिस ब्लाक, टॉवर–1, 6वीं मंजिल, एनबीसीसी कॉम्पलैक्स, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023 (भारत)
वेबसाइट : www.sjvn.nic.in

हिमाचल प्रदेश में विकास व परिवर्तन का नया युग

हिमाचल प्रदेश के 53वें पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सभी के लिए गर्व और हर्ष का अवसर है। 25 जनवरी, 1971 को इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शिमला के एतिहासिक रिज पर भारी बर्फबारी के बीच हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्ज़ा प्रदान किया था। उनके प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना।

हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और विकास पथ पर आगे ले जाने के लिए हिमाचल निर्माता एवं प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉ. यशवंत सिंह परमार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर मैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धाजंलि अर्पित करता हूं।

हमारी सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को जनता की सेवा करने का दायित्व सम्भाला और व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करना शुरू किया। हिमाचल प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। पिछली भाजपा सरकार से वर्तमान सरकार को 75000 करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला, जबकि कर्मचारियों को एरियर के रूप में 4430 करोड़ रुपए, पेंशनरों की देनदारी 5226 करोड़ रुपए तथा कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए एक हजार करोड़ रुपये बकाया है।

इसके अलावा, पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम 9 महीनों में बजट का प्रावधान किए बिना 900 संस्थान खोले और अपग्रेड किए। इससे प्रदेश पर 5000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ा।

कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों के दौरान अपने प्रतिज्ञा पत्र में दस गारंटियां दी हैं। इनमें से पहली गारंटी पुरानी पेंशन योजना की बहाली थी जिसे केबिनेट की पहली बैठक में ही पूरा कर दिया गया है।

एनपीएस के लगभग 8 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास फंसे पड़े हैं। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन देने का अपना वायदा पूरा किया है। इससे राज्य के लगभग 1.36 लाख एनपीएस कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

पुरानी पेंशन देने का प्रदेश सरकार का यह कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। हमारा इरादा है कि सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के आत्मसम्मान की रक्षा हो तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिले क्योंकि उन्होंने प्रदेश के विकास की गाथा लिखी है।

सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मैं सभी के बहुमूल्य योगदान की सराहना करता हूं। हम कर्मचारियों को डीए और पेंशनभोगियों को उनके लाभ प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं।

हमारे प्रतिज्ञा पत्र में युवाओं को एक लाख रोज़गार प्रदान करने और महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता देने का भी वायदा किया गया है। इन दोनों गारंटी को पूरी करने के लिए हमने मंत्रिमंडल की दो उप समितियों का गठन किया है जो एक महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

आज के इस शुभ अवसर पर मैं सभी सरकारी कर्मचारी भाईयों व बहनों से कहना चाहता हूं कि आप अंतिम पंक्ति में खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचें, जिन्हें अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है।

मैंने व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष देखा है। इसलिए आम आदमी की समस्याओं से भली-भांति परिचित हूं। उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार धरातल पर काम करेगी।

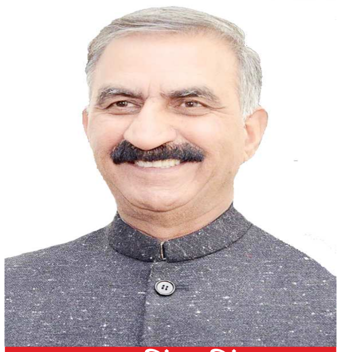

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू
मुख्यमंत्री (हिमाचल प्रदेश)

कर्ज के भारी बोझ के बावजूद प्रदेश सरकार अपने सभी वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ता के साथ काम कर रही है। इसके लिए कुछ कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है।

मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 4 वर्षों में हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। इसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार अपने सभी वादों को पूरा करेगी।

मैं कहता आया हूं कि हम सत्ता में सुख के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। व्यवस्था परिवर्तन रातों-रात नहीं हो सकता है।

भ्रष्टाचार के प्रति वर्तमान सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सत्ता संभालते ही हमने भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए कदम उठाने आरंभ कर दिए हैं।

परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर का कामकाज निलंबित किया जा चुका है और अब योग्यता के आधार पर ही निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन किया जाएगा।

वर्तमान सरकार के गठन को अभी 44 दिन का समय ही हुआ है। हमने अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप कार्य करने का प्रयास किया है। हमने जरूरतमंदों के लिए 101 करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री सुख-आश्रय सहायता कोष स्थापित किया है। सरकार ने यह कदम करुणा के लिए नहीं, बल्कि उनका अधिकार प्रदान करने के लिए उठाया है।

मैंने अपना पूरा वेतन और कांग्रेस के सभी विधायकों ने एक-एक लाख रुपए इस कोष में अंशदान दिया है। आईआईटी, एम्स, आईआईएम, आईआईआईटी, पॉलीटेक्निक, आईटीआई जैसे संस्थानों में दाखिला पाने वाले जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। उन्हें जेब खर्च भी दिया जाएगा।

प्रदेश सरकार वृद्धाश्रम, आश्रय गृह में रहने वाले बच्चों के लिए माता और पिता की भूमिका निभाएगी। सरकार, एकल महिलाओं एवं विशेष बच्चों को 10000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष वस्त्र अनुदान प्रदान करेगी।

बाल संरक्षण संस्थानों, वृद्ध आश्रमों, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन और विशेष गृहों में रहने वालों को लोहड़ी, मकर सक्रांति, होली और अन्य त्यौहार मनाने के लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपये का उत्सवभत्ता भी प्रदान कर रही है।

वर्तमान सरकार के छोटे से कार्यकाल में हमने व्यवस्था परिवर्तन की ओर अनेक कदम उठाए हैं। शिक्षा नीति में भी वर्तमान सरकार बड़े बदलाव और व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास कर रही है, जिससे गरीब बच्चों को पढ़ने और बढ़ने के समान अवसर मिल सकें। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे।

युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए नए तकनीकी कोर्स, जैसे कि रोबोटिक्स, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, आर्टफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कोर्स पॉलीटेक्निक, आईटीआई और इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू किए जाएंगे। सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार नई रोजगार नीति भी लाने जा रही है।

पर्यटन हमारी आर्थिकी का मुख्य जरिया है। प्राकृतिक, ग्रामीण, बागवानी, साहसिक तथा धार्मिक पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा ग्रामीण स्तर तक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पर्यटन परियोजनाओं को स्टार्ट-अप योजना से जोड़ा जाएगा।

निजी क्षेत्र में भी हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए वर्तमान सरकार निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। सरकार नई निवेश नीति लाएगी, जिसमें निवेशकों की सुविधा के लिए सरकारी बंधनों को कम किया जाएगा।

किसानों, पशुपालकों व बागवानों की आय में बढ़ोतरी करने की दिशा में भी सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश को फल राज्य के रूप में जाना जाता है। हमारी सरकार का संकल्प है कि कृषि और बागवानी के महत्व के दृष्टिगत किसानों और बागवानों के फलों की कीमत तय करने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

युवाओं को अपना उद्योग व कारोबार स्थापित करने के लिए बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।

हमारी सरकार ने प्रदेश के वातावरण को संरक्षित रखने के लिए जल विद्युत, हाईड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन करने तथा हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

प्रदेश में हरित उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे निर्यात में बढ़ौतरी होगी। सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में पांच सौ मैगावाट तक की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी।

प्रदेश सरकार ने राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का निर्णय भी लिया है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।

प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में जनता को श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि लोगों को अपने गंभीर रोगों के उपचार के लिए बाहरी राज्यों या प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं रहे।

आईजीएमसी, टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा दी जाएगी। मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी की जाएगी।

मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार को आप सभी का सक्रिय तथा रचनात्मक सहयोग प्राप्त होगा जिससे हमारे सुंदर प्रदेश में उन्नति और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर मैं, एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं तथा प्रदेश व आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि हम सत्ता के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, जिसमें आप सभी का सहयोग जरूरी है।

जय हिंद, जय हिमाचल।

प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर सम्भव सहयोग का आश्वासन दिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की।

प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रधानमंत्री से यह पहली भेंट थी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकास परियोजनाओं से सम्बंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए सभी परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए केद्र से उदारतापूर्वक सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को केद्र सरकार द्वारा आधारभूत संरचना को गति प्रदान करने के उद्देश्य से आरम्भ की गयी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना तथा रज्जू मार्ग के निर्माण के लिए पर्वतमाला योजना को प्रदेश में सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इन दोनों योजनाओं से प्रदेश के लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के अलावा सम्पर्क और अधोसंरचना विकास वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को हिमाचली शॉल, टोपी तथा स्मृति चिन्ह् भेंट कर सम्मानित किया।

प्रधानमंत्री ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी और प्रदेश को हर सम्भव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया।

मुख्यमंत्री ने केंद्र से प्रदेश में मौसम वेधशालाएं स्थापित करने का आग्रह किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में कृषि, बागवानी और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए अत्याधुनिक तकनीकें अपनाने और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसी एक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में न्यूक्लियर

मेडिसिन विभाग स्थापित करने पर विचार कर रही है ताकि कैंसर रोगियों को प्रदेश में ही रेडिएशन थैरेपी का उपचार प्रदान कर उनके समय और संसाधनों की बचत की जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने पर विशेष बल दिया जाना समय की मांग है और उन्होंने इसके लिए केंद्र से तकनीकी सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने राज्य के बागवानी और कृषि विभाग के अधिकारियों के लिए अनुकूलन (ओरिन्टेशन) कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही नई तकनीकों से परिचित करवाने में सहयोग का भी आग्रह किया जिससे उन्हें नवोन्वेषी तकनीकों से भलीभांति अवगत करवाया जा सकेगा। उन्होंने नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से किसानों और बागवानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाने का भी आग्रह किया, जिससे किसानों और बागवानों को उनके उत्पादों की गुणवत्ता को सुधारने में सहायता मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री ने 'आरोमा मिशन' के तहत लैवेंडर की खेती के लिए चम्बा जिला को शामिल करने और लैवेंडर के उत्पादन के लिए किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

प्राकृतिक आपदाओं के प्रति प्रदेश की संवेदनशीलता के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने भूकम्पीय क्षेत्रों कांगड़ा और हमीरपुर में एक उच्च स्तरीय अत्याधुनिक भूकम्पीय प्रयोगशाला एवं डॉटा विश्लेषण केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया।

उन्होंने डॉ. जितेंद्र सिंह को अवगत करवाया कि हिमाचल प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्याधिक संवेदनशील राज्य है। ऐसे में दो जनजातीय जिलों किन्नौर और लाहौल-स्पीति में डॉपलर राडार स्थापित करने के अलावा हमीरपुर, चंबा, नालागढ़, केलांग और काजा क्षेत्रों में मौसम वेधशालाएं (वेदर ऑबजरवेटरीज) स्थापित करने के साथ ही आपदा प्रतिक्रिया, विश्लेषण और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए हमीरपुर जिला में डॉटा सेंटर स्थापित करना अति आवश्यक है। इससे न केवल बहुमूल्य जीवन को सुरक्षित किया जा सकेगा अपितु राज्य के किसानों एवं बागवानों को मौसम सम्बंधी सटीक जानकारी समय पर उपलब्ध हो सकेगी।

डॉ. सिंह ने हिमालयी पारिस्थितिकी के प्रति मुख्यमंत्री की चिंता और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनकी गहरी रुचि की सराहना करते हुए उन्होंने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती और मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया भी उपस्थित थे।

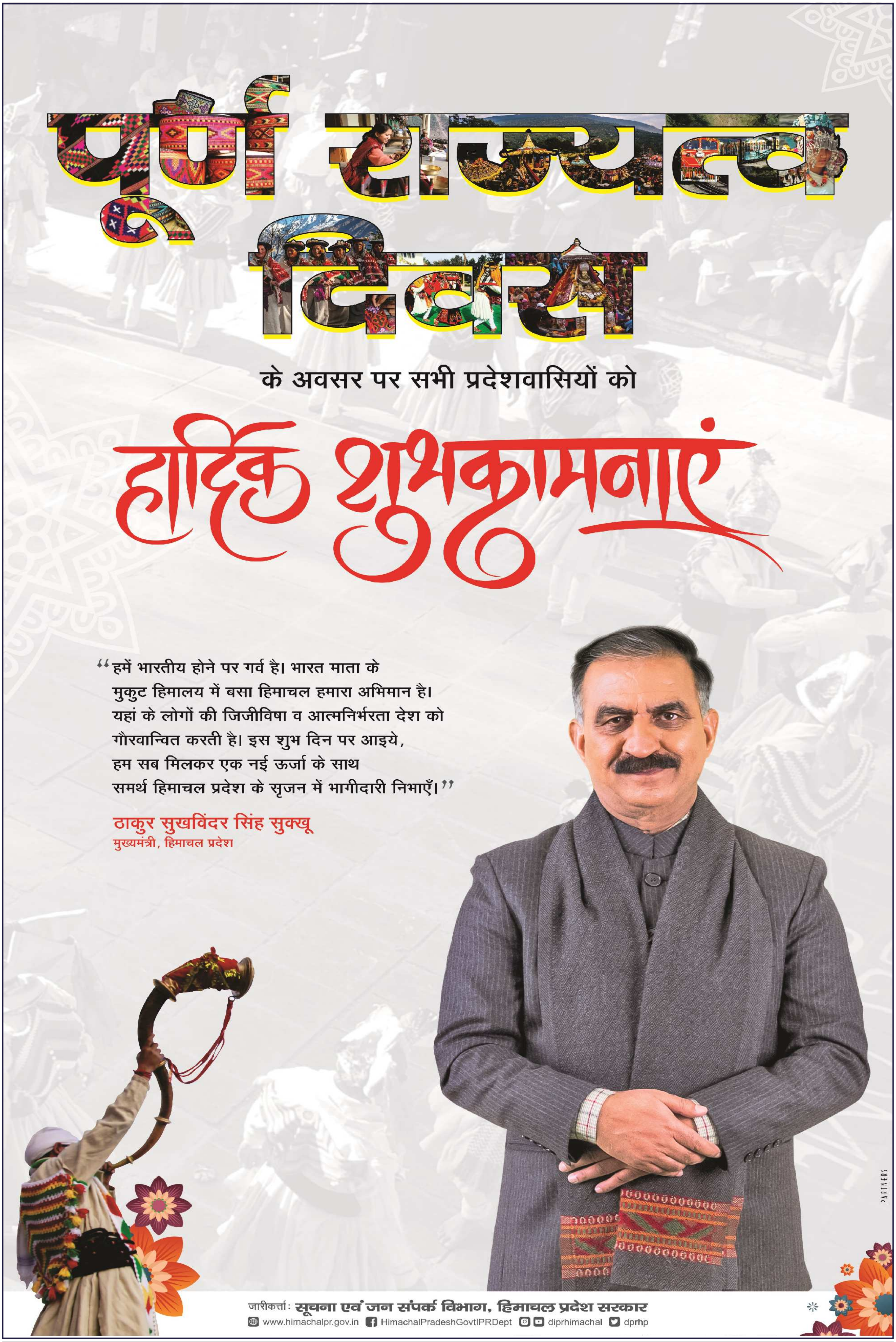

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

सीमेंट उद्योगों की तालाबन्दी वैध है या अवैध सरकार की इस पर चुप्पी सवालों में

कारखाना प्रबन्धन की ओर से सरकार को लिखे पत्र पर प्रशासन का मौन सवालों में

तालाबन्दी से पहले घाटे से उबरने के लिये सीमेंट प्रबन्धन के प्रयासों में प्रशासन की भूमिका भी सवालों में

शिमला/शैल। 14 दिसम्बर को प्रदेश के दाडलाघाट और बरमाणा स्थित सीमेंट कारखानों में अचानक घोषित हुई तालाबन्दी अब तक खुल नहीं पायी है। इस तालाबन्दी के कारण इससे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हजारों लोग अचानक प्रभावित हुये हैं। तालाबन्दी के कारण इन कारखानों में सीमेंट उत्पादन बन्द हो गया है। यह उत्पादन बन्द होने से इन कारखानों में सीधे काम करने वाले कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं। सीमेंट की ढुलाई में लगे ट्रक और उनसे जुड़े कर्मचारियो ट्रक मालिक सब बेरोजगार हो गये हैं। ट्रक आपरेटर बैंकों की किश्त नहीं चुका पा रहे हैं। इन कारखानों के कारण हजारों लोग दूसरे व्यापार धंधे कर रहे थे जो सब बेरोजगार होकर बैठ गये हैं। सरकार इस सीमेंट की सबसे बड़ी खरीददार थी। उत्पादन बन्द होने से सरकार के निर्माण कार्य प्रभावित हुये हैं। सरकार के साथ ही इस सीमेंट का उपभोक्ता आम आदमी की प्रभावित हुआ है। इस तरह यह तालाबन्दी प्रदेश की आर्थिकी पर एक सीधा और बड़ा प्रहार है। इसलिये तालाबन्दी से उठते सवाल सरकार और आम आदमी के लिये बड़े अहम हो जाते हैं। क्योंकि 11 दिसंबर को मुख्यमन्त्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमन्त्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने पद की शपथ ग्रहण की तथा 14 दिसम्बर को यह तालाबन्दी घोषित हो गयी। इस बीच बारह दिसम्बर को सुक्खू सरकार ने पूर्व जयराम सरकार के अंतिम छः माह में लिये फैसलों को पलटने का फैसला ले लिया।

स्मरणीय है कि कोविड काल में मोदी सरकार ने जब तीन कृषि कानून पारित किये थे तब उसी दौरान श्रम कानूनों में भी बदलाव कर दिया था। इस बदलाव से श्रमिकों के अधिकारों पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस बदलाव से उद्योग मालिकों को ही लाभ हुआ है। लेकिन इस बदलाव के कारण कारखानों में मालिकों/ प्रबन्धन द्वारा तालाबन्दी घोषित करने की औपचारिकताओं में बदलाव नहह आया है। तालाबन्दी घोषित करने से पहले उससे जुड़े कारणों और उन्हें हल करने के लिये किये गये प्रयासों की अधिकारिक जानकारी संबद्ध प्रशासन को दी जानी होती है। सीमेंट कारखानों को बन्द करने का कारण इसमें घाटा होना बताया गया है और घाटे का कारण सीमेंट ढुलाई के रेट ज्यादा होना कहा गया है। यदि इन कारणों को सही भी मान लिया जाये तो पहला सवाल यह उठता है कि अदाणी समूह ने 2022 में ही होलिसिम से 82000 करोड में यह कारखाने खरीदे हैं और इस लेन-देन में कोई टैक्स नहीं दिया गया है तो अदाणी को इस उद्योग में घाटा होने की जानकारी कब मिली। घाटा हटाने के क्या प्रयास किये गये और उनमें यहां काम कर रहे कर्मचारियों तथा ढुलाई से जुड़े ट्रक ऑपरेटरों की क्या भूमिका रही है। स्वाभिक है कि ऐसे सारे प्रयास करने और उनके विफल रहने

के बाद कारखाने के मालिक/प्रबन्धन को तालाबन्दी की नौबत आती है। तालाबन्दी से पहले क्या प्रबन्धन ने इस आशय की जानकारी संबद्ध प्रशासन को दी है या नहीं? इसकी कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आयी है। यदि ऐसी कोई पूर्व जानकारी प्रशासन के पास नहीं रही है तो यह तालाबन्दी सीधे अवैध हो जाती है और इसके लिए प्रबन्धन के खिलाफ आपराधिक कारवाई बनती है। लेकिन इस दिशा में सरकार की ओर से कोई कारवाई किये जाने के संकेत अब तक नहीं मिले हैं। जबकि कारखाना प्रबन्धन की ओर से पत्र बाहर आया है उसमें कहा गया है कि सीमेंट ढुलाई के लिए केवल 550 ट्रकों की आवश्यकता है जबकि इसमें 3311 ट्रक लगे हैं। इन्हें आने वाले दिनों में कम करने की आवश्यकता होगी।

दूसरी ओर यदि प्रशासन द्वारा किये गये प्रयासों पर नजर डाली जाये तो यह सामने आता है कि इसमें डी.सी. बिलासपुर पंकज राय और डी.सी. सोलन कृतिका कुल्हारी के स्तर पर वार्ता हुई। इसके बाद एस.डी.एम. अर्की और बिलासपुर के स्तर पर वार्ता हुई। लेकिन मामला नहीं सुलझा और निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति के स्तर पर वार्ता हुई और बेनतीजा रही। परिवहन सचिव आर.डी.नजीम के स्तर पर हुई वार्ता भी विफल रही। निदेशक खाद्य एवं आपूर्ति के.सी. चमन के स्तर पर एक उप समिति बनाई गयी। ढुलाई की दरें निर्धारित करने के लिये एक एजैन्सी की सेवाएं भी ली गयी। लेकिन सरकार के स्तर पर हुई यह सारी वार्ताएं विफल रहने के बाद 20 जनवरी को उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के स्तर पर हुई वार्ता भी विफल रही है।

उद्योग मंत्री के साथ भी वार्ता विफल रहने के बाद सारी वार्ताएं बन्द है और मामला मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया गया है। लेकिन इस सारे परिदृश्य में यह सवाल उठता है की सरकार तालाबन्दी की वैधता और अवैधता को लेकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रही है? यदि तालाबन्दी वैध है तो निश्चित है कि यह सब कुछ एक अरसे से शीर्ष प्रशासन के संज्ञान में चल रहा था। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि नई सरकार का गठन तो ग्यारह दिसम्बर को हुआ और तालाबन्दी 14 दिसम्बर को हो गयी तो क्या शीर्ष प्रशासन ने इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं दी है? यदि यह तालाबन्दी अवैध है तो सरकार अवैधता पर कारवाई क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इस पर सरकार के मौन से यह भ्रम भी पनप रहा है कि यह सारा मामला कहीं किसी बड़े राजनीतिक खेल की भूमिका तो नहीं बन रहा है?

यदि कौल सिंह चुनाव न हारते तो मुख्यमंत्री बनते प्रतिभा के ब्यान ने फिर हिलाई राजनीति

शिमला/शैल। राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाने के लिये कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। भारत जोड़ो यात्रा का कोई सीधा राजनीतिक लक्ष्य नहीं था जबकि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक है। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। वहीं पर यह भी आवश्यक है कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में एकजुटता का व्यवहारिक संदेश जाये। यह सवाल अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा वीरभद्र सिंह के मण्डी में उस वक्तव्य के बाद उभरा है जिसमें उन्होंने यह कहा कि यदि ठाकुर कौल सिंह विधानसभा चुनाव न हारते तो वह प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। यह बात सही हो सकती है लेकिन व्यवहारिक सच यह रहा है कि कांग्रेस ने यह चुनाव सामूहिक नेतृत्व तले लड़ा है। चुनावों से पहले और इनके दौरान किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया था। क्योंकि जयराम सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस के कई छोटे-बड़े नेताओं के भाजपा में जाने की चर्चाएं उठती रही हैं। कांग्रेस सदन के अंदर जितनी आक्रमक रही है उतनी आक्रमकता सदन के बाहर नहीं रख पायी है। कई बार तो सदन के अंदर की आक्रमकता तब के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर में व्यक्तिगत होने के कगार पर पहुंचती रही है। इसी आक्रमकता का परिणाम था की जयराम सरकार में कांग्रेस चारों उपचुनाव और दो नगर निगम जीत गया था। सदन के बाहर कांग्रेस संगठन में पदाधिकारियों की लंबी सूची बनाकर कुलदीप राठौर ने कार्यकर्ताओं को फील्ड में उतरने पर पहुंचा दिया था।

इस परिदृश्य में कांग्रेस हाईकमान ने सामूहिक नेतृत्व का सूत्र देकर किसी एक को नेता घोषित करने से परहेज किया था। अब जब सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनी और इसमें पहला मंत्रिमण्डल विस्तार हुआ तो इसमें तीन पद खाली रखने तथा मंत्रियों से पहले ही मुख्य संसदीय सचिवों को शपथ दिलाने की बाध्यता ने अनचाहे ही पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिये हैं। यही नहीं जिन गैर विधायकों को कैबिनेट रैंक में सरकार के अंदर जिम्मेदारियां दी गयी हैं उनमें कई वरिष्ठ नेताओं को इसमें जगह न मिल पाने से भी एकजुटता पर ही प्रश्नचिन्ह लगे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ के बाद मंत्रिमण्डल के विस्तार में लंबा समय लग जाने से इसी धारणा को बल मिला है।

ऐसे में जब पार्टी अध्यक्ष की ओर से पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता कौल सिंह को लेकर ऐसा ब्यान आयेगा तो दूसरे लोग निश्चित रूप से इसके राजनीतिक अर्थ ही निकालेंगे। क्योंकि कौल सिंह को उनकी वरीयता के अनुसार सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं मिल पायी है। अभी सरकार को शिमला नगर निगम के चुनावों का सामना करना है और निगम क्षेत्रों में ही पानी की दरें 10% बढ़ा दी गयी हैं। इससे पहले डीजल पर वैट बढ़ा दिया गया है। यह फैसले क्या सरकार के ही स्तर पर लिये गये हैं या इन्हें संगठन का भी अनुमोदन प्राप्त है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। जबकि चुनावों में सरकार से ज्यादा संगठन की भूमिका रहती है और इसमें सरकार के फैसले ही ज्यादा चर्चा में आते हैं। इस परिदृश्य में कांग्रेस के हर बड़े नेता का ब्यान चर्चा का विषय बनेगा ही। इस समय सरकार हर मंच पर वित्तीय कुप्रबन्धन और पिछली सरकार द्वारा हजारों करोड़ की वेतन और पैन्शन की जिम्मेदारियां छोड़ जाने का आरोप लगा रही है। लेकिन इस वित्तीय स्थिति से उबरने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है और इसमें संगठन की क्या भागीदारी है इस बारे में भी कोई ज्यादा जानकारी सामने नहीं है और यही आगे चलकर ऐसे ब्यानों की पृष्ठभूमि में कई सवालों को जन्म देगा।